

अफगानसितान मानवीय संकट

प्रलम्बिस् के लयि:

अफगानसितान, वशिव बैंक, दलिली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद, तालबान, इस्लामकि स्टेट ।

मेन्स के लयि:

भारत और इसके पड़ोसी, भारत के हतियों पर देशों की नीतियों और राजनीतिका प्रभाव, अफगानसितान संकट और उसके प्रभाव ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वशिव बैंक द्वारा अफगानसितान ट्रस्ट फंड में जमा (Frozen Afghanistan Trust Fund) 1 बलियिन अमेरिकी डॉलर का उपयोग देश (अफगानसितान) के बगिड़ते मानवीय स्थिति और आर्थिक संकट को कम करने के लयि शक्ति, कृषि, स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कार्यक्रमों के लयि उपयोग करने को मंजूरी दी गई है ।

- इसका उद्देश्य कमज़ोर लोगों की रक्षा करना, मानव पूंजी और प्रमुख आर्थिक एवं सामाजिक संस्थानों के संरक्षण में मदद करना और भविष्य में मानवीय सहायता की आवश्यकता को कम करना है ।
- इससे पहले [अफगानसितान पर दलिली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता](#) भारत में आयोजति की गई थी ।



प्रमुख बढि

अफगानसितान की वर्तमान स्थिति:

- अफगानसितान में व्याप्त अस्थिरता की स्थिति नि केवल इस क्षेत्र के लयि बल्कि पूरी दुनिया के लयि चतिजनक है ।
- अफगानसितान दशकों से अस्थिर और असुरक्षित रहा है, लेकिन [अगस्त 2021 में तालबान के सत्ता](#) में आने से पूरे क्षेत्र में एक नाजुक स्थिति बनी हुई है ।

- अफगानिस्तान में वर्तमान स्थिति 1990 के दशक के अंत में उत्पन्न भू-राजनीतिक परिदृश्य के ही समान है।
- वर्ष 1996 में तालबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने प्रतिमान के संभावित परिणामों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया।
- अंतरराष्ट्रीय वित्त सहायता प्रदान करने वाले संगठनों द्वारा अफगानिस्तान को अपनी सहायता देना बंद कर दिया है। तालबान सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ है। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र परतिकूल रूप से प्रभावित है।
- युद्ध से तबाह देश एक अभूतपूर्व मानवीय संकट का सामना कर रहा है, जो एक और हसिक संघर्ष में परिवर्तित हो सकता है।
- ग्रामीण आबादी के अलावा शहरों में रहने वाले अफगानों के लिये भी गुजारा करना असंभव हो रहा है।
- यदि तालबान आर्थिक स्थिति में सुधार करने में असमर्थ रहता है, तो अफगानिस्तान को एक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे स्थिति में तालबान का शासन काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है और देश में गृहयुद्ध छड़ सकता है।
- प्रायः आर्थिक उथल-पुथल का सामना कर रहे देश में आतंकवादी समूहों के लिये काम करना आसान होता है और अफगानिस्तान इसका कोई अपवाद नहीं है।

अफगानिस्तान में मानवीय संकट के प्रभाव:

- कई पश्चिमी देशों को लगता है कि अफगानिस्तान के कारण संपूर्ण विश्व पर एक तत्काल सुरक्षा खतरा पैदा हो गया है। तालबान, जो कि अंतरराष्ट्रीय मान्यता एवं वित्तीय सहायता हासिल करना चाहता है, हसिक तरीके अपनाए की तुलना में 'राजनयिक दृष्टिकोण' की ओर बढ़ रहा है लेकिन यह शांति लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती है।
 - यदि अफगानिस्तान में मानवीय संकट बढ़ता है, तो तालबान भी स्थितिका प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होगा, जैसा कि हसिक 'इस्लामिक स्टेट' (IS) के मामले में देखने को मिला था।
- अफगानिस्तान में एक संभावित हसिक संघर्ष क्षेत्र के अन्य देशों में फैल सकता है।
 - यदि ऐसा होता है, तो क्षेत्रीय शक्तियाँ अफगानिस्तान की सीमाओं के भीतर हसि को बनाए रखने के लिये प्रॉक्सी समूहों का समर्थन करना शुरू कर देंगी लेकिन यह अफगान संघर्ष का केवल एक अल्पकालिक समाधान होगा।
 - तालबान जतिना अधिक सत्ता में रहेगा, उसके लिये क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना उतना ही कठिन होगा।
- तालबान के अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों से संबंध हैं। सत्ता में उनकी वापसी ने क्षेत्र में जहादी संगठनों को उत्साहित किया है।
- जैसे-जैसे वे स्वयं को मज़बूत करेंगे, आतंकवाद के वित्तपोषकों और प्रायोजकों के साथ उनके सामरिक एवं रणनीतिक संबंध बढ़ेंगे जो अंततः इस क्षेत्र तथा उसके बाहर शांति एवं सुरक्षा को खतरे में डाल देगा।

अफगानिस्तान के लिये क्या किया जाना चाहिये?

- अफगानिस्तान में मानवीय संकट को केवल मानवीय सहायता से हल नहीं किया जा सकता है।
- अफगानों को गरीबी से बाहर निकालने के लिये अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है।
 - लेकिन अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिये अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तालबान के साथ जुड़ने की ज़रूरत है।
- यदि देश की मानवीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आतंकवाद अफगानिस्तान की सीमाओं से अन्य देशों तक भी पहुँच जाएगा।

भारत के लिये नहितार्थ:

- सामरिक चिंताएँ:
 - तालबान के नियंत्रण का मतलब पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों के लिये देश के परिणामों को प्रभावित करने हेतु एक बड़ा कारक साबित होगा, जो पिछले 20 वर्षों में भारतीय विकास और बुनियादी ढाँचा कार्यों हेतु बहुत छोटी-सी भूमिका का निर्वहन करता है।
- कट्टरपंथ का खतरा:
 - भारत के पड़ोस में बढ़ता कट्टरपंथ और अखलि इस्लामी आतंकवादी समूहों से क्षेत्र को खतरा है।

आगे की राह

- समावेशी सरकार: सभी जातीय समूहों की भागीदारी के साथ एक समावेशी सरकार के गठन के माध्यम से ही समस्या का समाधान हो सकता है।
- रूसी समर्थन: हाल के वर्षों में रूस ने तालबान के साथ संबंध विकसित किये हैं। तालबान के साथ किसी भी तरह के सीधे जुड़ाव में भारत को रूस के समर्थन की आवश्यकता होगी।
- चीन के साथ संबंध: भारत को अफगानिस्तान में राजनीतिक समाधान और स्थायी स्थिरता के उद्देश्य से चीन के साथ बातचीत करनी चाहिये।
- तालबान से वार्ता: तालबान से बातचीत करने से भारत नरिंतर विकास सहायता या अन्य प्रतिबद्धताओं के बदले विद्रोहियों से सुरक्षा गारंटी लेने के साथ-साथ पाकिस्तान से तालबान की स्वायत्तता का पता लगा सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

